



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1944 (श०)
(सं० पटना 862) पटना, मंगलवार, 18 अक्टूबर, 2022

सं० 16/स्था०-01-01/2021—4266/वि०
जल संसाधन विभाग

संकल्प
14 अक्टूबर 2022

विषय:- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण मामलों के अनुश्रवण एवं समन्वय, विभागीय परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण/संरक्षण एवं विभिन्न विभागों से भूमि हस्तांतरण मामलों के समन्वय आदि कार्यों हेतु सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा आधारित सेवा लेने हेतु भू-अर्जन विशेषज्ञ के 02 (दो) पदों के सृजन के संबंध में।

भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय के तहत कार्यरत आठ (8) विशेष भू-अर्जन कार्यालयों में आठ पदों के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सेवा के मात्र चार पदाधिकारी कार्यरत रहने के कारण भू-अर्जन से संबंधित कार्य हेतु उन्हें लगभग छः से सात जिलों के जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य करना पड़ रहा था। इतने बड़े क्षेत्राधिकार में एक पदाधिकारी के जिम्मे दो-दो कार्यालय का प्रभार होने से कार्य निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। साथ ही दिनांक-31.03.2019 के उपरांत भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी संलग्न विशेष भू-अर्जन कार्यालयों का अवधि विस्तार नहीं किया गया। इस कारण विभागीय संकल्प सह ज्ञापांक-1057 दिनांक-17.09.2019 एवं इसके अनुपालन में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1120 दिनांक-18.09.2019 द्वारा दिनांक-01.10.2019 के प्रभाव से जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्यरत भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी भू-अर्जन कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सृजन, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता है। सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत डैम/बराज से निःसृत नहर प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण की योजनाओं के अंतर्गत नदी तथा प्राकृतिक नालों के किनारों पर तटबंध, एंटी फ्लड स्लुईस तथा ड्रेनेज चैनल इत्यादि का निर्माण किया जाता है। जल संसाधन विभाग के उपरोक्त कार्यों के कार्यान्वयन हेतु बृहद स्तर पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए तटबंधों तथा नहरों के किनारों पर सड़कों का निर्माण भी कराया जाता है, जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता पड़ती है। नये उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बन्दोवस्ती

में पारदर्शिता अधिनियम-2013 के लागू होने के उपरान्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक श्रम साध्य हो गई है। उक्त अधिनियम में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA Work) एवं पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के कारण भू-अर्जन का कार्य काफी जटिल हो गया है। साथ ही विभाग की योजनाओं हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत भी रैयती भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई की जाती है।

उपर्युक्त नये उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बन्दोवस्ती में पारदर्शिता अधिनियम 2013 एवं बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत की जा रही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई/भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई का मुख्यालय स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय, अनुश्रवण तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन में समुचित सहयोग हेतु भूमि अधिग्रहण मामलों के जानकार एवं विशेषज्ञों का "भू-अर्जन कोषांग" गठित करना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त के आलोक में विभाग स्तर पर भू-अर्जन कोषांग के लिए निम्न पदों का सृजन किया गया है:-

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	योग्यता एवं अनुभव	मासिक मानदेय
1.	भू-अर्जन विशेषज्ञ Level-13	02 (दो)	भा०प्र०से०/ बि०प्र०से० के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी	सेवानिवृत्त अधिकारी को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता के योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवानिवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आएगा, वही राशि मानदेय/ संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा।

भू-अर्जन कोषांग हेतु कमरा, उपस्कर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन (मोबाईल) इत्यादि विभागीय स्थापना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

3. पद सृजन पर अनुमानित व्यय।- इन पदों के सृजन पर होने वाला कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रूपया-1935120/- (उन्नीस लाख पैंतीस हजार एक सौ बीस रूपये) लगभग है।

4. बजट शीर्ष।- इसका व्यय मुख्य शीर्ष-3451, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090, उप शीर्ष-0009, मांग संख्या-49, विपत्र कोड-49-34510009 00009, विषय शीर्ष- 2802 संविदा सेवायें (सिर्फ संविदा कर्मियों हेतु) ।

5. विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण मामलों के अनुश्रवण एवं समन्वय, विभागीय परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण/संरक्षण एवं विभिन्न विभागों से भूमि हस्तांतरण मामलों के समन्वय आदि कार्यों हेतु पृथक भू-अर्जन कोषांग गठित करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा आधारित सेवा लेने हेतु भू-अर्जन विशेषज्ञों के दो (2) पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अफजालूर रहमान,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 862-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>